संख्या 633 /V-2011-13(N)/2010

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।

आवास अनुभाग-1

देहरादूनः दिनांक ४५ 314 देश 2011.

विषयः रूद्रपुर बस स्टेशन व कार्यशाला की 1.674 हे0 नजूल भूमि उत्तराखण्ड परिवहन विषाग के नाम हस्तान्तरित करने विषयक। महोदयः

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—105/25—नजूल—परि०भू/2010 दिनांक 03—06—2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, रूद्रपुर बस स्टेशन व कार्यशाला हेतु 1.674 हेक्टेयर नजूल भूमि को नजूल नीति 2009 के प्रस्तर 4(ख)(1) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत (वित्त अनुभाग के शासनादेश संख्या—260/वित्त अनुभाग—3/2002 दिनांक 15—02—2002 के कम में) उत्तराखण्ड परिवहन विभाग, को उनके अनुरोध के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करते है।

- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2— जिस परियोजना के लिये भूमि हस्तान्तरित की जा रही हे वह एक अनुमोदित परियोजना हो ओर उसके लिये शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हैं।
- 3— हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग की जाये तो उसके लिये आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन से पुनः सहमित प्राप्त करनी होगा।
- 4— यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती है तो यह आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5— जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमित के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।



- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरांत यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो इसकी सूचना आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- प्रश्नगत भूमि वन से आच्छादित होने अथवा वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी०सी० शर्मा) प्रमुख सचिव।

संख्या 633(1)/V-3-17-/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।

2— प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादन।

🎤 निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

(डा० शैर्लेश कुमार पंत) अनुसचिव।